International Journal of Geography, Geology and Environment

P-ISSN: 2706-7483
E-ISSN: 2706-7491
IJGGE 2024; 6(1): 32-36
Received: 15-11-2023
Accepted: 19-12-2023

शिप्रा सिंह
शोधार्थी, भूगोल विभाग,
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य
विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान,
भारत

डॉ. अनीता माथुर
सेवानिवृत्त आचार्य, भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय रामगढ़,
अलवर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
शिप्रा सिंह
शोधार्थी, भूगोल विभाग,
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य
विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान,
भारत

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भौगोलिक विश्लेषण (2001–2018): जयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में

शिप्रा सिंह, डॉ. अनीता माथुर

सारांश
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति सुधारने एवं उन्हें बारहमासी सड़को से जोड़ने के उद्देश्य से तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की गयी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) प्रारम्भ में शत् प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना रही अर्थात् सम्पूर्ण वित्तीय खर्च केन्द्र सरकार करती थी। इस योजना के लिए हाई स्पीड़ ड़ीजल (एचएसडी) पर 50 प्रतिशत उपकर निर्धारित है। 1 मई 2013 से इस योजना में लागत को केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में कर दिया गया। ग्रामीण सड़क सम्पर्क में वृद्धि एवं सुधार के माध्यम से देश में आर्थिक व सामाजिक सेवाओं तक ग्रामवासियों की पहुँच का संवर्धन करते हुए, कृषि आय में बढ़ोतरी एवं रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी रूप से विकास करना अर्थात् यह गरीबी निवारण कार्यक्रम का एक प्रमुख भाग है। विगत दशकों में राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों के बावजूद आज भी लगभग 40 फीसदी ग्रामीण बसावटें बारहमासी सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं, इस समस्या के निवारण के लिए ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है।

कूटशब्दः बारहमासी सड़कें, गरीबी निवारण कार्यक्रम, हाई स्पीड़ ड़ीजल, ग्रमीण विकास

प्रस्तावना
भारत की सड़क परिवहन प्रणाली विश्व की तीसरी बड़ी सड़क परिवहन प्रणाली है। भारत के सड़क तन्त्र की सकल लम्बाई 3.35 मिलियन कि.मी. है। सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं उच्च मार्ग की लम्बाई 7310 किमी है। जयपुर जिले में बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण रोजगार के लिए प्रवास, शिक्षा प्राप्ति के लिए छात्रों का शहर में आना तथा उद्योगों की स्थापना मुख्य है। अतः जयपुर शहर पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं इस दबाव को सुनियोजित तरीके से प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। जयपुर जिले में कुल 13 तहसीले हैं, सभी तहसीलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है व उनके अन्तर्गत आने वाले गांवों को भी विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया है। योजना के तहत निर्मित सड़कों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया, यहाँ पर पड़ने वाले पुरातात्विक एवं पर्यटन को विश्व परिदृश्य पर लाने का काम किया जिससे इन रोजगार शून्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, लोक कला संस्कृति को देखने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक लाभ हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र
जयपुर शहर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर जिला राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक रूप में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यह राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। जयपुर जिला, प्रदेश के पूर्वी भाग में $26^0 23'$ से $27^0 51'$ उत्तरी अक्षांशों एवं $74^0 55'$ से $76^0 50'$ पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में सीकर व हरियाणा का महेन्द्रगढ़ जिला, दक्षिण में टोंक, पूर्व में अलवर, दौसा तथा पश्चिम में नागौर व अजमेर जिले स्थित हैं। जयपुर जिला समुद्री स्तर से 1417 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले में अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर–पश्चिम क्षेत्र से गुजरती है, यहां की जलवायु शुष्क एवं स्वास्थ्यवर्धक है। अरावली पर्वत श्रेणी मानसून रेखा के समान्तर होने के कारण यहां वर्षा कम होती है। जयपुर में वर्षा का औसत 60.35 सेन्टीमीटर है, शीतकाल में यहाँ (मावठ) वर्षा होती है। जनवरी का तापमान 8^0 से 10^0 तक होता है। जयपुर जिले में वर्ष 2011 में 955.66 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घेरे हुए था। इस जिले में वर्षा ऋतु में केवल मौसमी नदियाँ ही प्रवाहित होती हैं, जिनमें बाणगंगा, मांसी, बाण्डी, साबी, मेण्ढा, ढूंढ व सोता प्रमुख नदियाँ हैं। जिले में उच्च जनसंख्या घनत्व अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिफल है।

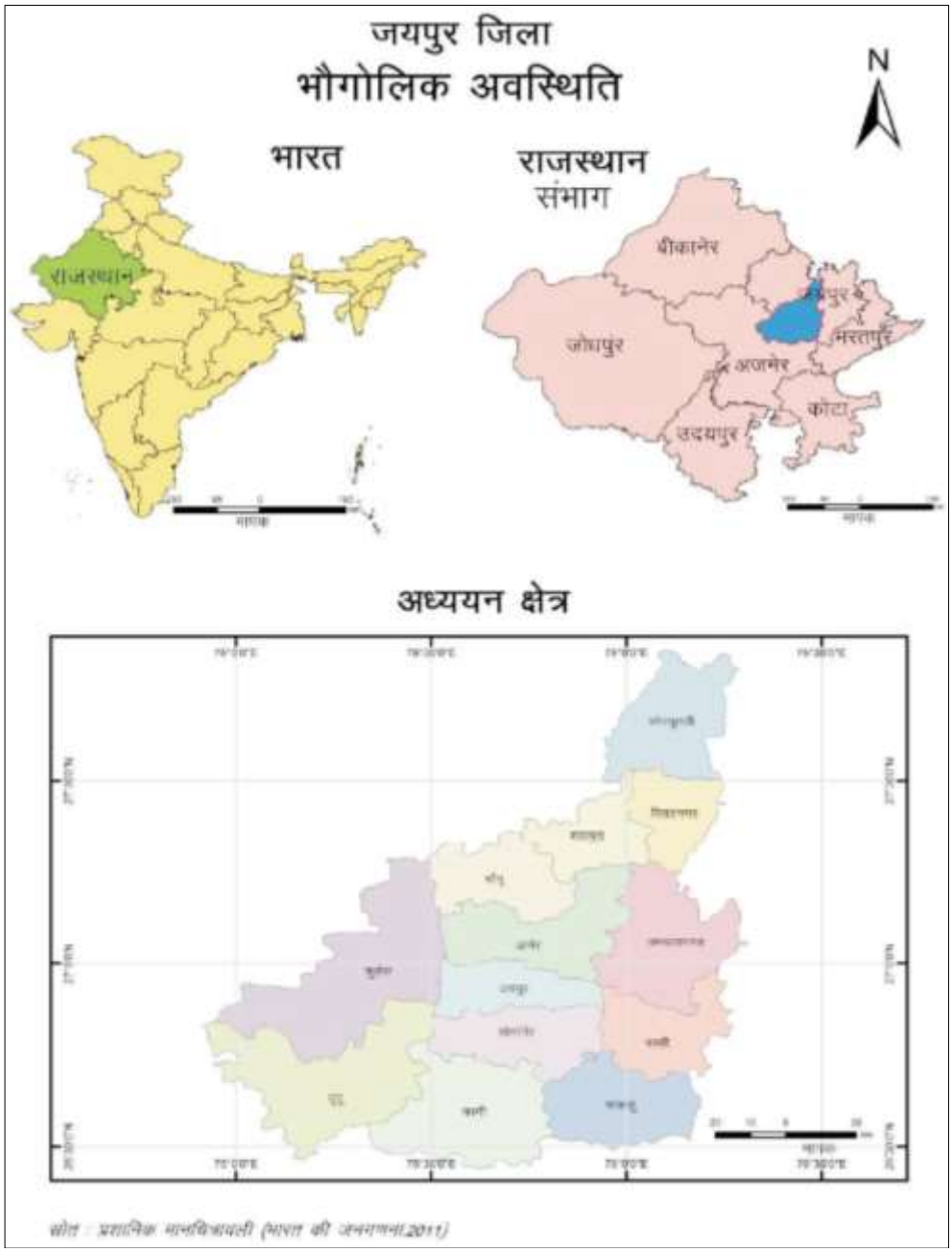

मानचित्र 1: जयपुर जिले की अवस्थिति

उद्देश्य

1. जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत अनुमानित लागत एवं खर्च का अध्ययन करना।
2. जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का तीव्र विकास हुआ है।

शोध विधि

उक्त अध्ययन में उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए विषय पर उपलब्ध साहित्य से सम्बन्धित पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की सूचनाएँ सरकारी कार्यालयों से एकत्रित करके विश्लेषित की गयी हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सामग्री तथा आंकड़ों का एकत्रीकरण निम्नलिखित स्रोतों से किया गया है –

1. **प्राथमिक स्रोतः** इस सम्बन्ध में प्रश्नावली, परिचर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया है।
2. **द्वितीय स्रोतः** इस सम्बन्ध में प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों, कार्यालयों के प्रगति प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है।

जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश में केन्द्र सरकार द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारम्भ किया गया, इस प्रकार जयपुर जिले में भी इस योजना की शुरूआत हुई। इस योजना के तहत जयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी रूप से वर्ष भर सुचारू परिवहन योग्य अर्थात् बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सड़कों का निर्माण किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। जयपुर जिले में सामान्यतः पीएमजीएसवाई में निर्मित सड़कों की

चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जाती है, जिसमें 3.75 मीटर (12 फीट) हिस्सा ड़ामर वाला होता है, बाकि हिस्सा ग्रेवल का होता है, कई परिस्थितियों में इन सड़कों की चाड़ाई 6 मीटर भी होती है, जिसमें ड़ामर वाला हिस्सा 3 मीटर का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जयपुर जिले की सभी तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों की 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों, ढ़ाणियों एवं गांवों को बारहमासी सडकों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। यह योजना सरकार द्वारा संचालित गरीबी निवारण कार्यक्रम का भी एक मुख्य भाग है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच गुणवत्तायुक्त परिवहन मार्ग विकसित कर, जिले में फसल उत्पादन में वृद्धि लाना, साथ ही फसल उत्पादों, फल, सब्जी एवं दुग्ध की कम समय में आपूर्ति शहरों एवं अन्य क्षेत्रों में करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

जयपुर जिले की सभी 13 तहसीलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2000–01 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण सम्बंधी कार्यों की शुरूआत कर दी गयी थी। इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों की 500 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटों को बारहमासी सडकों के माध्यम से सड़क संपर्क उपलब्ध करवाना है, जयपुर जिले की सभी तहसीलों के गांव मुख्यरूप से मैदानी क्षेत्र में आते है, इस कारण यहाँ जिन भी न्यूनतम 500 आबादी वाली ग्रामीण बसावटों का सड़क सम्पर्क नहीं है वहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्राथमिकता अनुसार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जिले में वर्ष 2000–01 में कुल 11 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसको बढ़ा कर वर्ष 2001–02 में 55 कर दिया गया, इस प्रकार प्रति वर्ष स्वीकृत सड़कों की संख्या में वृद्धि होती रही है।

इस योजना में स्वीकृत कार्यों को निश्चित समयावधि में पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर लगातार मोनिटरिंग की जाती है। वर्ष 2010–11 तक कुल 572 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसको बढ़ा कर वर्ष 2011–12 में 583 कर दिया गया। जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों की संख्या वर्ष 2017–18 तक 828 पहुँच गयी है एवं वर्ष 2018–19 तक यह 851 हो चुकी है। जिले में बेहतर परिवहन मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

तालिका 1: जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रगति (2000–01 से 2018–19)

वर्ष	सड़क संख्या	स्वीकृत		पूर्ण		प्रगति	
		सड़क लम्बाई (किमी)	परियोजना लागत (करोड़ रू.)	सड़क लम्बाई (किमी)	परियोजना खर्च (करोड़ रू.)	सड़क लम्बाई (प्रतिशत)	परियोजना खर्च (प्रतिशत)
2000–01	23	71	2	37	1	52	50
2001–02	55	130	10	44	4	34	40
2002–03	132	336	31	68	16	20	52
2003–04	198	506	33	254	20	50	61
2004–05	198	506	57	330	35	65	62
2005–06	271	695	91	368	67	52	73
2006–07	468	1233	177	536	139	43	78
2007–08	550	1687	277	1263	188	74	68
2008–09	570	2052	371	1523	289	74	77
2009–10	572	2093	380	1796	328	85	86
2010–11	572	2093	390	2023	361	96	93
2011–12	583	2133	408	2092	367	98	90
2012–13	655	2315	428	2098	377	90	87
2013–14	802	2676	520	2188	404	81	78
2014–15	802	2676	530	2253	433	77	82
2015–16	802	2686	540	2472	507	92	93
2016–17	806	2686	545	2580	530	96	97
2017–18	828	2838	580	2704	539	95	94
2018–19	851	2838	600	2838	597	100	99

स्त्रोतः पीएमजीएसवाई, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, वर्ष 2001–2019

आरेख 1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की संख्या

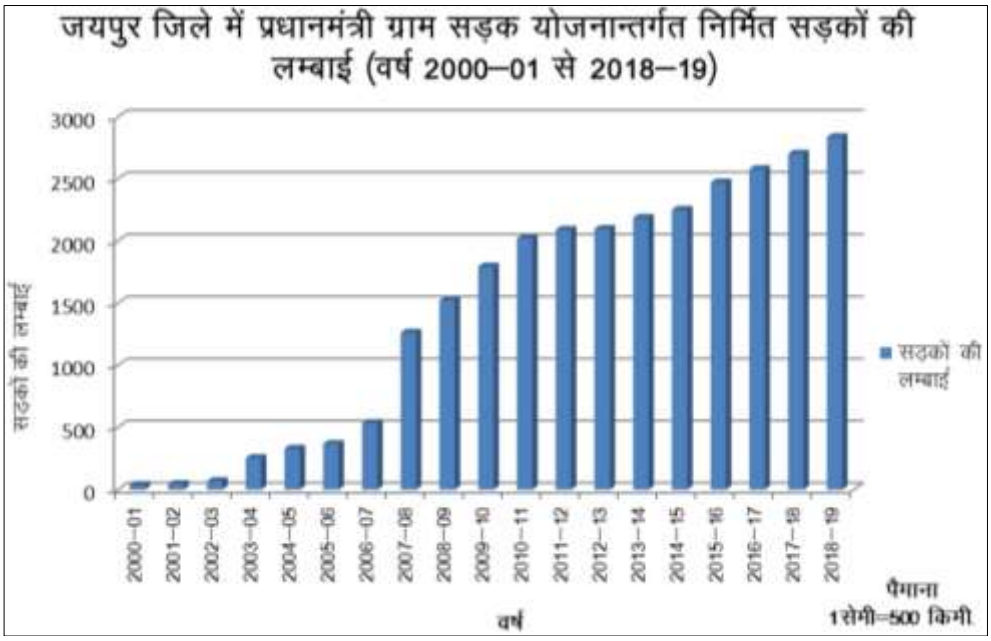

आरेख 2: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई

जयपुर जिले में वर्ष 2000–01 में सड़कों की स्वीकृत लम्बाई 71 किमी. एवं परियोजना लागत 2 करोड़ रूपये रखी गयी, जिनको बढ़ा कर वर्ष 2001–02 में क्रमशः 130 किमी. एवं 10 करोड़ रूपये कर दिया गया, इस प्रकार प्रति वर्ष स्वीकृत सड़कों की लम्बाई एवं परियोजना लागत में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2010–11 तक स्वीकृत सड़कों की लम्बाई 2093 किमी. एवं परियोजना लागत 390 करोड़ रूपये हो गयी थी, जिसको बढ़ा कर वर्ष 2011–12 में क्रमशः 2133 किमी. एवं 408 करोड़ रूपये कर दिया गया। जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों की लम्बाई वर्ष 2017–18 तक 2838 किमी. एवं परियोजना लागत 580 करोड़ रूपये पहुँच गयी है, जिनमें वर्ष 2018–19 तक सड़कों की स्वीकृत लम्बाई को तो 2838 किमी. ही रखा गया तथा परियोजना लागत को 600 करोड़ रूपये कर दिया गया।

जिले में वर्ष 2000–01 में सड़कों का कुल निर्माण 37 किमी. एवं परियोजना खर्च 1 करोड़ किया गया, जो कि वर्ष 2001–02 में क्रमशः 44 किमी. एवं 4 करोड़ रूपये रहे, इस प्रकार प्रति वर्ष सड़कों का निर्माण एवं परियोजना खर्च में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2010–11 तक सड़कों का निर्माण 2023 किमी. एवं परियोजना खर्च 361 करोड़ रूपये हो गया, जिसको बढ़ा कर वर्ष 2011–12 में क्रमशः 2092 किमी. एवं 367 करोड़ रूपये कर दिया गया। जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल सड़कों का निर्माण वर्ष 2017–18 तक 2704 किमी. एवं परियोजना खर्च 539 करोड़ रूपये पहुँच गया, यह वर्ष 2018–19 तक क्रमशः 2838 किमी. तथा 597 करोड़ रूपये कर दिया गया।

जिले में वर्ष 2000–01 में सड़कों की स्वीकृत लम्बाई की अपेक्षा निर्माण 52 प्रतिशत एवं परियोजना की स्वीकृत लागत की अपेक्षा खर्च 50 प्रतिशत किया गया, जो कि वर्ष 2001–02 में क्रमशः 34 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रहे, इस प्रकार प्रति वर्ष सड़कों का निर्माण एवं परियोजना खर्च में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2010–11 तक सड़कों की स्वीकृत लम्बाई की अपेक्षा निर्माण 96 प्रतिशत एवं परियोजना की स्वीकृत लागत की अपेक्षा खर्च 93 प्रतिशत हुआ, जो कि वर्ष 2011–12 में क्रमशः 98 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत रहा। जयपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की स्वीकृत लम्बाई की अपेक्षा निर्माण वर्ष 2017–18 तक 95 एवं परियोजना की स्वीकृत लागत की अपेक्षा खर्च 94 प्रतिशत पहुँच गया, यह वर्ष 2018–19 तक क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत हो गये।

निष्कर्ष

जयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से सम्पूर्ण देश की भांति ही 25 दिसम्बर 2000 को केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को स्थायी रूप से वर्ष भर सुचारू परिवहन योग्य अर्थात् बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जयपुर जिले में वर्ष 2000–01 में कुल 11 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसको बढ़ा कर वर्ष 2018–19 तक 851 कर दिया गया, इस प्रकार प्रति वर्ष स्वीकृत सड़कों की संख्या में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2000–01 में सड़कों की स्वीकृत लम्बाई 71 किमी. एवं परियोजना लागत 2 करोड़ रूपये रखी गयी, जिनकों वर्ष 2018–19 तक क्रमशः 2838 किमी. तथा 600 करोड़ रूपये कर दिया गया। जिले में वर्ष 2000–01 में सड़कों का कुल निर्माण 37 किमी. एवं परियोजना खर्च 1 करोड़ किया गया, जो कि वर्ष 2018–19 तक क्रमशः 2838 किमी. तथा 597 करोड़ रूपये कर दिया गया। इस प्रकार वर्ष 2000–01 में सड़कों की स्वीकृत लम्बाई की अपेक्षा निर्माण 52 प्रतिशत एवं परियोजना की स्वीकृत लागत की अपेक्षा खर्च 50 प्रतिशत हुआ, जो कि वर्ष 2018–19 तक क्रमशः 100 प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत हो गये हैं। इस प्रकार जिले में सड़कों का तीव्र गति से निर्माण किया गया है, जिससे जिले में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तीव्रता आई है।

सन्दर्भ सूची

1. गौतम अल्का (2023) "आर्थिक भूगोल के मूल तत्व "शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज, पृ. सं. 113–126।
2. राय मुकेश (2022) "ट्रांसपोर्टेशन इंजिनियरिंग" एकूमैन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. सं. 36–56।
3. सक्सेना, हरिमोहन (2021),''राजस्थान का भूगोल'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, राजस्थान सरकार पृ. सं. 79–87।
4. सौम्या के, भट जयराम (2021) "परफॉरमेंस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) इन रूरल रोड़ कनेक्टिविटी – ए स्टेड़ी", जनरल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस एण्ड़ इनोवेटिव रिसर्च, वोल्यूम 8, इश्यू 7

5. बालामुरूगन जे (2020) "रोल ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) इन रूरल ड़वलपमेंट", जनरल ऑफ सोशियल वेलफेयर एण्ड़ मैनेजमेंट, वोल्यूम 12, इश्यू 2
6. शर्मा, एच.एस., शर्मा, एम.एल. (2020), राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. सं. 47–58।
7. जिला साख्यिकी रूपरेखा, जयपुर जिला– वर्ष 2001–2019
8. मिचल ए. एम. (2019) 'ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस,' विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नई दिल्ली, पृ. सं. 62–72।
9. कौशिक देवेश (2012), "परिवहन भूगोल" अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. सं. 51–63।
10. http://pmgsy.nic.in
11. http://omms.nic.in